



न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह

वाद सं०-93/2023

राम प्रसाद ठाकुर वगैरह

बनाम

राजेन्द्र ठाकुर वगैरह

(धारा-144 दं०प्र०सं०)

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
बारे में
टिप्पणी
तिथि सहित

या
रिख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

6.06.2023

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन पत्र एवं तत्सम्बन्धी थाना प्रभारी, बेंगाबाद थाना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्ष के विरुद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं०प्र०सं० की धारा-144(i) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण-पृच्छा की मांग की गई :-

भूमि की विवरण:-मौजा-खुटाबांध थाना-बेंगाबाद जिला-गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं० 11 प्लॉट नं० 86 रकवा 40 डी० तथा चौहदी-उ०-गैरमजरूआ जमीन। द०-नीज जमीन आवेदक का प्लॉट नं० 87 पू०-पी०सी०सी० रोड़, प०-आवेदक की माता सुकरी की जमीन।

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष संख्या 01 द्वारा अपना-अपना कारण-पृच्छा/कागजात समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष का दावा है कि तुलसी हजाम, हरिहर ठाकुर एवं चन्द्रिका ठाकुर ने संयुक्त रूप से खाता नं० 11 एवं 09 प्लॉट नं० 86 के अन्तर्गत 40 डी० जमीन सहित अन्य कुल 2.00 (दो एकड़) जमीन बजरिए निबंधित केवाला के वर्ष 1972 में संजीदा खातुन से क्रय किया एवं दखलकार हुआ तथा दाखिल-खारीज के पश्चात सरकार को लगान का भुगतान कर सरकारी लगान रसीद हासिल किया। तुलसी हजाम अपने तीन लड़के-राम प्रसाद ठाकुर, राधेश्याम ठाकुर एवं सहदेव ठाकुर को छोड़कर मरे, जो इस वाद में प्रथम पक्ष के सदस्य है। हरिहर ठाकुर अपने तीन लड़के-राजेन्द्र ठाकुर, सुरेन्द्र ठाकुर एवं महेन्द्र ठाकुर (द्वितीय पक्ष संख्या 01 से 03) को छोड़कर मरे। चन्द्रिका ठाकुर अपने तीन लड़के-अनिल ठाकुर, सुनिल ठाकुर एवं रतन ठाकुर (द्वितीय पक्ष संख्या 04 से 06) को छोड़कर फौत कर गए। इस प्रकार उभय पक्ष के सदस्य संयुक्त रूप से अपने सुविधानुसार उपरोक्त भूमि को उपयोग में ला रहे हैं, परन्तु द्वितीय पक्ष के सदस्य पार्वती देवी के नाम से जाली एवं बनावटी कागजात तैयार कर प्रथम पक्ष की जमीन

को हथियाना चाहते हैं। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कि तुलसी ठाकुर एवं हरिहर ठाकुर ने संयुक्त रूप से प्लॉट नं० 86 एवं 23 अन्तर्गत 20 डी० जमीन मुकरी देवी के साथ बिक्री किया है। द्वितीय पक्ष के सदस्य प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन हथियाना चाहते हैं।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात की छायाप्रतियाँ दाखिल किया गया है :-

1. संजीव खानू द्वारा तुलसी हजाम वगैरह के पक्ष में निष्पादित केवाला का इन्डेन्स।
2. तुलसी ठाकुर वगैरह द्वारा मुकरी देवी के पक्ष में निष्पादित केवाला।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष संख्या 01 का कहना है कि इनकी माँ-पार्वती देवी को प्लॉट नं० 86 की जमीन 50 साल पूर्व बजरिए खरीदगी के हासिल है एवं खरीदगी से ही उक्त जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं तथा सरकारी मालगुजारी रसीद कटवाते चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कागजात जाली एवं बनावटी है। मुकरी देवी के साथ 20 डी० जमीन बिक्री किए जाने की बात बिल्कुल गलत है। मुकरी देवी का उक्त भूमि पर कोई दखल-कब्जा नहीं है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम पक्ष द्वारा आज तक कोई केवाला दाखिल नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष की माँ ने चाहरदिवारी का निर्माण की है एवं वर्तमान में इनके लड़का मकान का निर्माण कर रहे थे, जिसको लेकर प्रथम पक्ष के सदस्य द्वितीय पक्ष को तंग-तबाह कर रहे हैं। विज्ञ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि तुलसी हजाम वगैरह द्वारा वर्ष 1972 में क्रय की गई भूमि को सही मान भी लिया जाता है, तो उक्त जमीन के तीन हिस्सा में एक हिस्सा द्वितीय पक्ष संख्या 01 से 03 तक का बनता है।

द्वितीय पक्ष संख्या 01 द्वारा निम्नांकित कागजात की छायाप्रतियाँ दाखिल किया गया है :-

1. पंजी-2 का कम्प्यूटर जनित प्रति।
2. सरकारी लगान रसीद का कम्प्यूटर जनित प्रति।

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष संख्या 01 के विज्ञ अधिवक्ताओं का दलील सूना एवं प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष संख्या 01 द्वारा समर्पित

कारण-पृष्ठा / कार
खानू द्वारा तुलसी ह
वादागत भूमि पर कि
जबकि द्वितीय
गई उक्त
पुलि

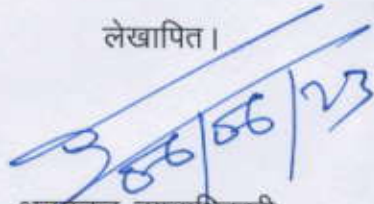
2

सुनवाई के दौरान
से प्लॉट नं० 86 एवं 23
की किया है। द्वितीय पक्ष के
कित कागजात की
केवाला

कारण-पृच्छा/कागजात का सुक्ष्मावलोकन किया। प्रथम पक्ष के सदस्य संजीदा खातून द्वारा तुलसी हजाम वगैरह के पक्ष में निष्पादित केवाला के आधार पर वादगत भूमि पर हिस्सा चाहते हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस प्रतिवेदन से भी होती है, जबकि द्वितीय पक्ष संख्या 01 का दावा इनकी माँ-पार्वती देवी द्वारा क्रय की गई उक्त जमीन के आधार पर है। अभिलेख के साथ संचित कारण-पृच्छा एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपना हिस्सा चाहते हैं, जिसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस मामले का निराकरण हेतु प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।



अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।



अनुमंडल दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।